The Criminal Law (Amendment) Bill, 2018

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI KIREN RIJIJU): Sir, I move:

That the Bill further to amend the Indian Penal Code, Indian Evidence Act, 1872, the Code of Criminal Procedure, 1973 and the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.

सर, मैं बिल को सदन के समक्ष रखते समय सिर्फ दो मिनट बोलना चाहूंगा कि पिछले कुछ महीनों में हमें देखने को मिला है कि हमारे देश में नाबालिग लड़कियों के साथ ऐसी हृदयविदारक बलात्कार की घटनाएं देखने को मिली हैं, जिनकी वजह से देश भर में और हमारे राजनीतिक दलों में भी यह बात उठी है कि ऐसे बलात्कारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। यह मुद्दा कई राज्यों ने भी उठाया है कि इसके संबंध में हमारे कानून में मृत्युदंड की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसी आवाज उठने के बाद सदन नहीं चल रहा था, इसलिए सरकार ने एक Ordinance लाने का निर्णय किया।

MR. CHAIRMAN: Ministers and Members, please sit in your places. What is happening to this House? I am not able to understand this. I thought it was the Rajya Sabha.

SHRI ANAND SHARMA: Sir, there is no order.

MR. CHAIRMAN: No, no. But this is not the order. I have been telling the Ministers also. Next time I will have to name them. Don't create that situation. One has to come quietly into the House, take his seat, do his work and then, quietly leave and do whatever he wants to do outside, not inside. I have said this at least three times. I really feel sorry for everybody, including Members. Some Members have developed a new problem of sitting and standing. Sitting and standing cannot be done together. That is known to everybody. I have been in this House for the last 19 years. I am seeing a new trend here. Some people are also trying to teach me what the Chair needs to do, by preaching against the rules. Teaching and preaching against the rules is not allowed. That should be noted by everybody. Whoever has got a problem can go out; there is no problem at all. Now, the Minister, Shri Kiren Rijiju.

SHRI KIREN RIJIJU: Sir, for the information of this august House, since the Government had brought the Criminal Law (Amendment) Ordinance, 2018, four States have already brought laws in their respective Assemblies, awarding capital punishment for those who commit rape on a girl child under the age of 12. Those States are Madhya Pradesh, Rajasthan, Haryana and Arunachal Pradesh.

Sir, briefly, I would like to inform this august House that we have introduced certain amendments in the Indian Penal Code, the Criminal Procedure Code as well as the Indian Evidence Act. Also, there are consequential effects on the Prevention of Children from sexual offences law as well. So, without going into details, I will be responding to the interventions from the various hon. Members. I would like to place the Criminal Law (Amendment) Bill, 2018 before this august House for consideration.

The question was proposed.

MR. CHAIRMAN: There is one amendment by Prof. M.V. Rajeev Gowda. ...*(Interruptions)*...

SHRI NEERAJ SHEKHAR (Uttar Pradesh): Sir, Vandana Chavanji wants to say something. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI VANDANA CHAVAN (Maharashtra) Sir, I want to make a request to the Hon. Chairman. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Vandanaji, what is the issue?

SHRIMATI VANDANA CHAVAN: Sir, I want to make a request that this Bill is an extremely sensitive Bill which seeks to address the atrocities on children. Sir, earlier there was Indian Penal Code but very lately we have formulated a special provision for children, that is, POCSO. Sir. in this Bill, we are seeking to move amendments being brought under the Indian Penal Code. Since there is a special provision for children. I seek your intervention, Sir, that this be sent to a Select Committee. These amendments should come under the POCSO and not under the Indian Penal Code. Therefore, it should be sent to a Select Committee. That is my request. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: You have got your right to request but it is for the Government to accept it or not. Now, Shri Ravi Prakash Verma to speak on the Bill. आप लोगों ने नाम भेजने हैं।

श्री रवि प्रकाश वर्मा (उत्तर प्रदेश): सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का मौका दिया है।

श्री सभापति: आप समय को ध्यान में रखकर आगे बढ़िए।

श्री रवि प्रकाश वर्मा: सर, जैसा कि अभी वंदना जी भी कह रही थीं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और बच्चों के लिए बहुत ही स्पेशल प्रावधान पार्लियामेंट ने बनाकर दिए हैं। सर, यह ऐसा issue है, जिस पर विरोध करने की कोई गुंजाइश नहीं है। ...

MR. CHAIRMAN: One minute; I have asked Prof. Rajeev Gowda to move the amendment. बीच में disturbance होती है, जिसकी वजह से diversion होता है। वर्मा जी, आप एक मिनट बैठ जाइए। मैं आपको इसके बाद बुलाता हूं।

PROF. M.V. RAJEEV GOWDA (Karnataka): Mr. Chairman, Sir, this is an extremely important issue and we must take serious action against offenders who victimise children and perpetrate sexual offences against them. But there are certain failings in this Bill which is why I am urging that the Minister and the House sends it to the Select Committee. I want to make three or four points very quickly. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: No. That is later on. ...*(Interruptions)*...

PROF. M.V. RAJEEV GOWDA: Sir, if I cannot convince the House, how can I urge the House to pass my amendment? ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: You understand ...*(Interruptions)*...

PROF. M.V. RAJEEV GOWDA: For that to happen, I have to convince the House. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: We have been there in this House. ...*(Interruptions)*... You have to follow the procedure. ...*(Interruptions)*... There is one Amendment by Prof. M.V. Rajeev Gowda for reference of the Criminal Law (Amendment) Bill, 2018 to the Select Committee of the Rajya Sabha. The Member may move his Amendment at this stage without any speech. That is the rule position. Are you moving your Amendment or not?

PROF. M.V. RAJEEV GOWDA: Sir, I am not moving it.

MR. CHAIRMAN: Thank you. The motion for consideration of the Criminal Law (Amendment) Bill, 2018 is now open for discussion. ...*(Interruptions)*... I have no other way than going by the rules and procedures laid down so far. Now, Shri Ravi Prakash Verma to speak on the Bill.

श्री रवि प्रकाश वर्मा: सर, मैं अपनी बात दोहराना चाहता हूं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और मेरा अनुमान है कि पूरा सदन इस पर पूरी गंभीरता के साथ विचार करेगा। हमारे हिन्दुस्तान में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। इस तरह की खबरों से रोज़ अखबार भरे रहते हैं। कोई दिन बाकी नहीं जाता है, जब महिलाओं के प्रति और बच्चों के प्रति यौन दुर्व्यवहार की खबरें समाचार पत्रों में नहीं आती हैं। इस मुद्दे पर कोई मतभेद भी नहीं है कि जो दुराचारी हैं, उनको कठोर सजा मिलनी चाहिए। सरकार ने जो अमेंडमेंट्स किए हैं, उन अमेंडमेंट्स में, किसी को कोई ऐतराज़ भी नहीं है।

सर, जो मृत्युदंड की बात कही जा रही है, मैं यहां पर एक बात बिल्कुल साफ कह देना चाहता हूं कि जो छोटे बच्चे हैं, क्योंकि हम लोगों ने इस पर काफी काम किया है, खास तौर से जो छोटे बच्चों के साथ में यौन उत्पीड़न की घटनाएं घट रही हैं, तीन साल के बच्चे, चार साल के बच्चे, पांच साल के बच्चे, छह, सात, आठ और दस साल के बच्चों के साथ में जो भी घटनाएं होती हैं, उनको करने वाले परिवार के ही जान-पहचान के, उनके नज़दीकी लोग ही होते हैं, ज्यादातर केसेज़ में उनके परिवार के और नज़दीकी लोग ही शामिल होते हैं और इन मामलों को दबाया जाता है। महोदय, सजाएं बढ़ाई गई हैं, IPC, CrPC, Evidence Act और POCSO में जो amendments किए जा रहे हैं, वह बात समझ में आती है। जो महिलाएं हैं, जिनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, बलात्कार किए जा रहे हैं, उन अपराधों में 7 साल से बढ़ाकर सज़ा 10 साल की जा रही है। जो 16 साल की बच्चियां हैं, उनके साथ किए जाने वाले अपराधों में सज़ा 20 साल या आयुपर्यन्त की गई है। 12 साल की उम्र से छोटे बच्चों के साथ किए जाने वाले अपराधों में 20 वर्ष से आयुपर्यन्त सजा की गई है और मृत्यु दंड का प्रावधान भी रखा गया है।

महोदय, rarest of the rare cases में कोर्ट के पास यह प्रावधान सुरक्षित रहता है कि जिन केसेज़ में बच्चों की मौत हो जाती है या फिर वे vegetative state में चले जाते हैं, उनमें सजा-ए-मौत दी जाए। ऐसा पहले भी हुआ है। Act में इस तरह का प्रावधान करने से मुझे लगता है कि एक दूसरे किस्म का संदेश जाएगा और मैं बताना चाहता हूं कि जो victim हुए हैं, वे आज अपनी बात उठाने लगे हैं और मुंह खोलने लगे हैं तथा वे इस बात को कहते हैं कि हम चाहते हैं - जिन लोगों ने गड़बड़ की है या गलत काम किए हैं, उनका ट्रीटमेंट हो। उन्हें सजा मिले और उनकी मानसिकता को सुधारने का काम किया जाए, न कि उन्हें सज़ा-ए-मौत का काम किया जाए।

मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का यह थोड़ा सा populist move है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि निर्भया केस के बाद, जिन लड़कियों के साथ बलात्कार होते हैं, अपराधी उन्हें जान से मार देते हैं। हमें यह भी डर है कि बच्चों के साथ भी कहीं ऐसा ही न हो। यह बहुत गम्भीर मामला है। मैं इस बात को बहुत समय से कहता आ रहा हूं कि अब समय आ गया है कि हम अपने समाज को और जितने भी हमारे institutions हैं, उन्हें child-centric बनाएं। हिन्दुस्तान child centric country बने, जहां हम बच्चों को तवज्जह दें। उन बच्चों को हम अच्छी शिक्षा दे पाएं, उन्हें अच्छा माहौल दे पाएं, उन्हें अच्छा रहन-सहन का तरीका दे पाएं और इस प्रकार हम उन्हें इज्ज़त की जिंदगी जीने का रास्ता दे पाएं, लेकिन अभी तक हम इसमें कामयाब नहीं हुए हैं।

महोदय, मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे issues हैं, खास तौर पर जो शिक्षा से जुड़े issues हैं। मैं आज माननीय मंत्री जी और सरकार से भी आग्रह करना चाहता हूं कि ये जो बच्चे हैं, वे कहीं न कहीं उपेक्षा का शिकार हुए हैं। राज्य की तरफ से भी, समाज की तरफ से और कहीं-कहीं परिवार की तरफ से भी भारी उपेक्षाएं बच्चों ने बर्दाशत की हैं। इसका प्रतिफल यह हुआ है कि हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, जो कल तक victim थे, आज perpetrators हो गए हैं। बड़ी अजीब सी बात है कि जो बच्चे अपनी छोटी उम्र में victimization के शिकार हुए थे, उनमें से बहुत से ऐसे बच्चे हैं, जो अपराधी बन चुके हैं। यह जो चक्र है, इसे हमें समझना पड़ेगा। कई विशेषज्ञों द्वारा इसके ऊपर बड़ी-बड़ी studies की गई हैं। जस्टिस वर्मा कमीशन ने भी इस बात पर चर्चा की थी कि जो पेनल्टी के प्रावधान रखे जा रहे हैं, उन्हें

[श्री रवि प्रकाश वर्मा]

कैसा रखा जाए? जो सजा के प्रावधान सख्त किए गए हैं, वे स्वागत योग्य हैं। सजाएं बढ़ाई गई हैं, वह भी स्वागत योग्य है। जो बार-बार गुनाह करते हैं या आदतन गुनाह के आदी हैं, उन्हें आयुपर्यन्त, जो उनकी नैचुरल लाइफ है, पूरे समय उन्हें जेल में रखा जाए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं सज़ा-ए-मौत के मामले में एक बार माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वे इस पर पुनः विचार कर लें, क्योंकि यह बात बहुत उपयुक्त नहीं है।

महोदय, एक बात और समझ में आ रही है कि जो घटनाएं छोटे बच्चों के साथ घट रही है, जो यौन दुर्व्यवहार हो रहे हैं, उनमें boys भी हैं और girls भी हैं। हमारा जो law बन रहा है वह लड़कियों के मामलों को तो address कर रहा है, लेकिन boys के मामलों को address नहीं कर रहा है। सर, मुझे यह देख कर बड़ा डर लग रहा है, क्योंकि हिन्दुस्तान में एक तरफ ऐसी लॉबी चल रही है, जो IPC के सेक्शन 377 को हटाने की बात कर रही है और दूसरी तरफ आज जब हम Special Act की बात कर रहे हैं और हमें बच्चों को protection देना है, तो उसमें बच्चों को इस purview से बाहर रखा गया है। सर, हमारे पास जो जानकारी है, उसके अनुसार इस पर बहुत researches हुई हैं और experts ने इस बात को बताया है। बाल कल्याण मंत्रालय के अध्ययन के अनुसार यौन उत्पीड़न के शिकार होने वाले करीब 53 प्रतिशत boys हैं, तो इसे gender neutral कैसे कर सकते हैं? जब हम बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, तो हमें उसी समग्रता में सोचना चाहिए। मैं आपके समर्थन में हूं।

महोदय, आपने इसमें जो trial का time कम किया है, यह बहुत अच्छा काम किया है। चार्जशीट दाखिल करने का समय आपने दो महीने कर दिया, पूरा ट्रायल खत्म कर दिया, यह अच्छा है। यदि आप इसे और भी कम कर पाएं, तो और अच्छा होगा। अनुभव बताता है कि ऐसे मामलों में Special Courts बना कर के कई मामलों में trial एक महीने में पूरा किया गया है। मुझे लगता है कि इससे कुछ संदेश जाएगा। सर अभी-अभी, कुछ दिनों पहले Thomson Reuters Foundation ने पूरी दुनिया में एक रिपोर्ट जारी की है। उनके पास लगभग 500, 550 एक्सपर्ट्स हैं, जो पूरी दुनिया में हैं। वे सर्वे करते रहते हैं और उन्होंने इस बात को घोषित किया है कि हिंदुस्तान महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा असुरक्षित देश है। सर, यह बहुत ही चिंताजनक है। ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Let us not quote those reports which are not substantiated and unnecessary ruin the image of our country.

SHRI RAVI PRAKASH VERMA: Sir, it is a news item.

MR. CHAIRMAN: You do not understand the consequence. मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री रवि प्रकाश वर्मा: सभापति जी, मैं सिर्फ ...**(व्यवधान)**... बात करना चाहता हूं। ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: But we ourselves should not encourage ...*(Interruptions)*... पूरे देश का होगा, किसी व्यक्ति या किसी पार्टी का नहीं होगा। ...**(व्यवधान)**...

श्री रवि प्रकाश वर्मा: सभापति जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हम लोग ऐसे लोग नहीं हैं। सच्चाई यह है कि हम लोग ऐसे लोग नहीं हैं, लेकिन हम शुतुरमुर्ग बनकर भी नहीं जी सकते। हमारे आस-पास जो घटनाएं घट रही हैं, उनके लिए समाज जिम्मेदार नहीं है, उनके लिए परिवार जिम्मेदार नहीं है, उनके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं। यह बहुत दुखद स्थिति है।

सभापति जी, मैं कई बार सदन में, लोक सभा में भी और राज्य सभा में भी यह कह चुका हूं कि इसी संसद ने, 1975 में इस बात को रिजॉल्व किया था कि बच्चे हमारे देश के सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संसाधन हैं। उसके बाद ये खबरें सामने आ रही हैं और यह कानून सामने आ रहा है। सर, यह देखकर दिल टूटता है। पता नहीं, लोग क्यों नहीं समझते हैं? सवाल यह है कि यह मैसेज जमीन तक, नीचे तक जाता क्यों नहीं? जो लोग इग्नोरेंस में हैं, अंधेरे में हैं, जो लोग एक ऐसी मानसिक स्थिति में जी रहे हैं कि उन्हें जुल्म करने के बाद ऐसा लगता ही नहीं है कि हमने कोई जुल्म किया है। सर, इस बात को बहुत गहराई से देखने की जरूरत है। हम लोग दिल्ली में, पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं, हम केवल clerical या statistical बेसिस पर बात नहीं कर सकते हैं। अगर एक भी बच्चा किसी atrocity का शिकार बनता है, तो इस पर हमारी जिम्मेदारी बनती है, पार्लियामेंट की जिम्मेदारी बनती है, हम उससे बच नहीं सकते हैं।

सर, मैं सरकार से भी आग्रह करना चाहता हूं कि आप अपने आने वाले समय को इस्तेमाल करें और हिंदुस्तान को चाइल्ड फ्रेंडली स्टेट बनाने की कोशिश करें। जो बजटिंग है, वह child budgeting हो, child-focussed planning हो।

सर, यह देश कब तक पिछड़ा बना रहेगा? हमारे ये बच्चे, जिनकी आज की तारीख में 22-25 करोड़ की तादाद है और नौजवान साथी मिलाकर तो 46 करोड़ से ऊपर है, ये अंधेरे में घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, इनको रास्ता नहीं मिल रहा है। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि हम किसी एक दिन मौका निकालकर इन बच्चों के मुद्दों पर एक स्पेसिफिक डे devote करके पूरी बहस दिखाएं।

सर, ये हमारे बच्चे हैं और अगर इन बच्चों के साथ, इन नौजवानों के साथ यह देश अच्छा सुलूक करेगा, उनको महत्व देगा, जिम्मेदारी देगा, तो ये बच्चे हिंदुस्तान को पिछड़े देश से एक विकसित देश बनाने की ताकत रखते हैं।

सर, मैं ज्यादा बातें नहीं कहना चाहता हूं, हालांकि मामला बहुत महत्वपूर्ण है, जितना समझा जाए, उतना कम है, किंतु मेरा माननीय मंत्री जी से और इस सरकार से यह आग्रह है कि अपनी आंखें और कान खोलें और बच्चों को वह महत्व दे, जो प्रत्येक परिवार में बच्चे को मिलना चाहिए, जिससे कि हिंदुस्तान तरक्कीयाफ्ता बन सके। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।

PROF. M.V. RAJEEV GOWDA: Sir, I represent Karnataka in this House, which has enacted a very progressive child protection policy. Having said that, it is a matter of great concern, in fact, I must say that it is a matter of great shame that we have sexual offences against children. Our conscience is shaken every time we hear about such stories that demonstrate that there is a sickness in our society. It is urgent that we enact laws that address this problem. But, earlier, I was trying to argue that the Minister should

[Prof. M.V. Rajeev Gowda]

work with the House and refer this Bill to the Select Committee, not just for the sake of Parliamentary scrutiny, but because we also want to improve the law in numerous ways. This opportunity to speak now is giving me a chance to elaborate, which, in your wisdom, you did not give me earlier.

MR. CHAIRMAN: Rules did not provide for that. You now have ample opportunity. Go ahead.

PROF. M.V. RAJEEV GOWDA: Sir, my first argument is that, as Vandana Chavanji has already pointed out, there is a law, the POCSO law, which deals with these particular kinds of offences. Now, when you look at the evidence of the implementation of the POCSO law, there is a lot to be desired. Even before that, let me point out that here, we are focussing on the accused, but we also have to focus on the victims - how to prevent not just the atrocities but also how to prevent further victimisation through the process that will be put in place by the changes that we are bringing in. Sir, under POCSO, what you find is that the rate of conviction has fallen from 32.6 per cent to 28.2 per cent; the pendency of cases has risen from 81.3 per cent to 89.6 per cent; speedy justice is not being delivered by the Special Courts and the Special Prosecutors are not being assigned to these cases. And, we must understand that the victims are children. When they are put in a situation where they have to attend court proceedings and have to face the people who have harmed them or are accused of harming them, they can often turn hostile. They find that situation extremely difficult to cope with. Sir, there is also a situation that a lot of children discontinue their education, they are maimed and scarred for life as a result of this. They may have to move and their families may have to move. So a lot of issues need to be considered while passing these kinds of amendments to the criminal laws and that is one of the reasons why I say let us go deeper into this. My suggestions are very constructive, please pay attention to these.

The second reason, as also been raised by the previous speaker, Shri Ravi Prakash Verma, and that has to do with male and female victims. Sir, you cannot create a discrepancy in the law. If you look at increasing punishment for offences against minor girls, there are minor boys also who are affected as victims of sexual crimes. In 2007, the Ministry of Women and Child Development did a sample study of 12,000 children and found that 53 per cent of the victims, the majority of them were boys. Why is the Minister not paying attention to these kinds of statistics that are out there in the hands of different Ministries? Sir, we have also paid attention substantially in this House, to

the third gender. The third gender is also affected by sexual offences, and we must pay attention. I urge the Home Minister, to pay attention to these kind of changes that need to be addressed in this criminal law amendment.

Sir, the third major reason has to do with how the Bill discriminates between the punishment for sexual offences against girls under sixteen and other vulnerable sections of women. Sir, these women could be pregnant women, women with disabilities who are also victims of sexual crimes. How come we have a set of punishments different for sexual offenders of those vulnerable groups when they are victimised, while a different set of punishments for sexual offenders of girls under sixteen? Sir, those are also vulnerable communities. We must pay attention to their needs and ensure that there is equal protection given to them.

Sir one more thing, in terms of practical reality, sentencing is at the discretion of judges. When there is a very long sentence that is prescribed, typically judges will go for a minimum sentence. When something like that happens, the purpose of this whole amendment and the desire of society to unleash the power of law on these perpetrators is lost. Further, the death penalty can result in again a higher standard of evidence, etc., being required which could also result in perpetrators getting off. So, these all are the issues that could have been taken into consideration. We could have brought experts in to testify before the Select Committee and, Sir, even now I urge the Minister and the Minister of State for Home Affairs to think about the fact that this law needs to be strengthened and what we are saying is very much in the spirit of improving the law and making sure that we have a better protection regime for sexual crimes against children.

Shri Ravi Prakash Verma talked about how lowering the time for investigation from three to two months is a good thing. I would like to argue that these are complex issues and I am not sure that in a hurried manner we will be able to pay attention to all the complexities, level of evidence required etc., and, therefore, I am not sure that this had to be the case all the time. So, I would urge the Government to consider these constructive points that I have made and even now refer this Bill to the Select Committee. ...*(Interruptions)*... Let me just finish. I am finishing.

MR. CHAIRMAN: He is just finishing.

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल): महोदय, मैं सिर्फ यह प्रस्ताव रखता हूं कि इस बिल को पारित करने के लिए सदन का समय तीन घंटे या जब तक बिल पास हो, तब तक के लिए बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापतिः ठीक है।

6.00 P.M.

SHRI BHUBANESWAR KALITA (Assam): Sir, if more time is needed on this Bill, we can go on.

PROF. M. V. RAJEEV GOWDA: Sir, I just want to summarise. We are all supportive of action against those who perpetrate sexual crimes on children. However, the Bill can be strengthened, the rights of the victims can be addressed, discrepancies between boy and girl victims can be addressed, vulnerable groups can also be given equal protection and practical aspects of how the law is actually implemented can be considered. I urge the Minister to even now move it to the Select Committee, and we will ensure that we will have an even stronger Bill.

श्रीमती रूपा गांगुली (नाम निर्देशित): ऑनरेबल चेयरमैन सर, आपने मुझे इस बिल पर अपनी बात रखने के लिए मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। जब यह Ordinance लाया गया था, उस वक्त सेशन नहीं चल रहा था और एक के बाद एक, बहुत सारी घटनाएं हो रही थीं, इसलिए हमारे देश के प्रधान मंत्री महोदय और मंत्री महोदय, सबने मिल कर, बैठक करके यह Ordinance जारी किया था। उसी के बाद आज यह बिल के रूप में यहां हमारे सामने आया।

सर, महिलाओं पर निर्दयता, महिलाओं पर atrocities, महिलाओं के असम्मान, बच्चों के ऊपर निर्दयता, ये सारी बातें बहुत सालों से हमारे देश में हो रही थीं। कभी समाज का रोग, कभी परिस्थिति का शिकार, कभी कुछ, कभी कुछ कह कर बहुत सालों से हम लोग इसे स्वीकारते आए हैं। यह कड़ा step बहुत लोगों को knee jerking लग रहा था और लग रहा है, इस बारे में बहुत सारी रिपोर्ट्स भी आई हैं। लोगों ने कहा कि इसकी क्या जरूरत है, इसके बारे में और भी चर्चा की जा सकती है। सही बात है, चर्चा हमेशा अच्छा काम ही करती है, यह मैं मानती हूं, लेकिन इसके साथ यह भी सच है कि इस देश में इतने सारे laws, इतने सारे आईन हमेशा से थे और उनमें amendments भी होते रहे हैं, यह कोई नई बात नहीं है। जब भी ऐसी घटनाएं घटीं, जब कभी भी हम ऐसे किसी घटना स्थल पर पहुंचे, जहां एक छोटी सी बच्ची के ऊपर ऐसी निर्दयता होती है, रेप होता है, तब भी क्या हम लोगों में यह सोच आ सकती है कि जिन लोगों ने gang-rape किया है, उनके भी human rights होने चाहिए? हम मानते हैं कि civic देश में नियम के अनुसार human rights की बातें, जब अपराधी पकड़े जाते हैं और जब उनकी death penalty की बात आती है, तभी की जाती हैं। सर, हम इतनी ही उम्मीद करेंगे और आपके जरिए सदन में सबसे यह बात कहने की कोशिश करेंगे कि सिर्फ एक बार मुंह मोड़ कर देख लें कि ये जो छोटी बच्चियां हैं, ये हमारी खुद की बेटियां हैं या हमारी बहन की बेटियां हैं और ऐसे वक्त में इन लोगों पर क्या बीतती है। हम जैसे लोग, जो यहां सदन में बहुत बड़े नेतृत्व के पद पर हैं, जिन्होंने activism किए हैं और गांव-गांव जाकर लोगों के पास खड़े हुए हैं, हम सबने कभी न कभी ज़रूर ऐसे experiences किए हैं। भाई साहब, हमने खुद भी ऐसे experiences किए हैं, इसलिए हम आप सभी से यह कहना चाहेंगे कि उन बच्चों पर और उनके परिवार वालों पर क्या बीतती है, ये वही जानते हैं। हम वहां पर केवल दो मिनट रुककर चले आएं या दो घंटे बैठ कर चले आएं अथवा फिर दस दिन अवस्थान करके, सबको पकड़वा दें, इससे कुछ नहीं होता है। वह दुःख, वह असम्मान, वह दर्द उन बच्चों के दिल से और उनके परिवार के लोगों के दिल से कभी नहीं उतरता है। बहुत-बहुत सालों

तक उनके ज़हन में वह बैठा रहता है, उनके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है और उनको अपनी बाकी जिन्दगी के साथ cope-up करने में दिक्कत हो जाती है। हम लोगों को उम्मीद है कि ऐसे वक्त में यह बिल पूरे देश में एक ऐसा माहौल पैदा कर सकता है, जिससे लोग इस प्रकार का कृत्य करने से पहले दस बार नहीं पचास बार सोचेंगे। Pedophiles जैसे लोग और जो pervert mentality के लोग हैं, उनके लिए कभी-कभार यह बोला जाता है कि यह तो एक मानसिक विकृति है अथवा इसी प्रकार की दूसरी explanation दी जाती हैं। वे इस प्रकार का कृत्य, ज़िदगी भर और सालों-साल तक इसी तरह से करते आए, क्योंकि उनको पता है कि घर की छोटी भतीजी है, इसलिए वह किसी को इसके बारे में बोल नहीं पाएगी, उसे चाचा-चाचा या मामा-मामा करके बुलाते हुए हमारे पास आना ही पड़ेगा। एक बार पकड़े जायें, तो भारी-भरकम सज़ा मिलेगी, यह बात लोगों के ज़ेहन में बैठ जानी चाहिए। आज इस देश में ऐसी घटना पैदा करने वाले, घटना बनाने वाले, करने वाले जो लड़के हैं, जो youth भी हैं, जो बड़े भी हैं और जो senior भी हैं सभी लोगों के ज़ेहन में यह बात बैठ जानी चाहिए कि अगर पकड़े गये तो मृत्युदंड मिलेगा।

मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों से बस यही उम्मीद रखूंगी कि एक बार अपने परिवार, अपने दोस्त, अपनी बहन, अपने रिश्तेदारों की ओर एक बार मूंह मोड़ कर देखें कि अगर कभी ऐसा किसी को झेलना पड़े, तो उसकी feeling कैसी रही होगी। आगे से इस देश में कोई ऐसी हिम्मत नहीं करे, यही सोच कर हमारे देश के प्रधान मंत्री जी यह एक Ordinance लाये थे। यह बिल हम पेश कर रहे हैं। हम इस बिल के साथ हैं और हम उम्मीद रखेंगे कि सब हमारे साथ ही रहेंगे। प्रणाम, नमस्कार।

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN (Tamil Nadu): I think because of recent incidents the Government issued the Ordinance and now it 1 has brought the Bill.

Subject to correction, under section 173 of the CrPC, the investigation has to be completed within a period of two months for the offences for which the Bill has been brought. I think it is a double-edged weapon. One way to see it is that it may be concluded without finding out the real culprit. Another way to see it is that in haste a wrong person may be implicated.

Clause 23(1A) says, "The presence of the informant or any person authorised by him shall be obligatory at the time of hearing of the application for bail to the person under sub-section (3) of Section 376 or Section 376AB or Section 376 DA or Section 376DB of the Indian Penal code." I think the victim must be given an opportunity. It should not be the informant.

The conviction rate is very, very low in our criminal justice delivery system. It is a well-known fact. The main fact for the low rate of conviction in our criminal justice delivery system is witnesses turning hostile. Initially witnesses support the prosecution, but during the trial they turn hostile. That is why prosecuting agency is not able to secure conviction. Also, in this kind of an offence, the informant may support the victim or may

[Shri A. Navaneethakrishnan]

not support the victim. Initially he may file a complaint and finally he may turn back. So, the presence of the informant or any person authorised by him is also a welcome one. At the same time, I hope the victim or the guardian of the victim may be given an opportunity to be present at the time of consideration of bail. The opportunity to oppose or to make her submission is a must, subject to correction, and I leave it to the Home Ministry.

There are other aspects where enhanced punishment has been contemplated and mandatory punishment has also been given. Remission is a constitutional right. Under the Indian Constitution, in certain cases, the President or the Governor has been given the power to remit the sentences. Even after a sentence is confirmed by the Supreme Court, it can be altered or reduced by the President or the Governor which in turn is the Government. But now there is this mandatory provision which I may be permitted to read. For example, Section 376AB says, "Whoever commits rape on a woman under twelve years of age shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than twenty years, but which may extend to imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life, and with fine or with death. Provided that such fine shall be just and reasonable to meet the medical expenses and rehabilitation of the victim. Provided further that any fine imposed under this section shall be paid to the victim." So, now, subject to correction, the issue is, whether the Constitutional power given to the President and the Governor is taken away or not. It is very clearly mentioned that the imprisonment for life means imprisonment for the remainder of the person's natural life. So, under the provision of the Criminal Procedure Code, normally the State Governments detain a person convicted for life sentence only up to 12 years. Depending upon the facts and circumstances and the conduct of the convicted person, the sentence is reduced to 12 years. If a person is confined to jail for a maximum period, he is released; that too, on birth anniversaries of great leaders. That is happening. It is an annual event or feature. In our State also, it is happening. Now, my humble submission to the hon. Home Minister is this. He is a great leader. I want to have some clarification. Is the remission power conferred under the Constitution to the President and the Governor still available or not? ...*(Interruptions)*... He is a great leader. He is present. I can't say like that. It is my doubt. Subject to correction, I may be wrong. Even if the death is awarded which is confirmed by the Supreme Court, the President can intervene. There is no doubt about it. Also, subject to correction, the term 'woman' has been employed in certain expressions in the Bill. I think a girl below 12 years cannot be termed as woman. She is a girl child. I think that is appropriate. I may be wrong.

Sir, I support the Bill because of what is happening now and also at international levels, there is no safety for women. That is the view propagated. I welcome this Bill. Thank you.

MR. CHAIRMAN: Now, Shri Sukhendu Sekhar Ray. Originally, you had eleven minutes, but now there is a suggestion. I leave it to your better sense.

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY (West Bengal): Sir, Lawyers should get some more time on such Bills.

Sir, whatever Shrimati Roopa Ganguly, Prof. Rajeev Gowda and Shrimati Vandana Chavan have said, I concur with their views. However, I would like to make a few points. As my good friend, Mr. Navaneethakrishnan, has rightly pointed out, in Clauses 4, 5 and 6, the expressions which have been used are 'woman under sixteen years of age', 'woman under twelve years of age', etc. Now, Sir, according to the Oxford English Dictionary, an adult human female is a woman and a girl is a female child. Then, as per definition, a child is a young human being below the age of puberty or below the legal age of majority. Keeping in view all these expressions and definitions provide of or in the English Dictionary, I think this word 'woman' should be replaced by appropriate words. There are certain more legal shortcomings in this Bill. I support the request that has been made by Mr. Gowda that the Bill should go to the Select Committee because there are so many shortcomings.

Take for example, — this is my personal view on this Bill — in case of rape of a woman below 12 years, the punishment is minimum 20 years and maximum life imprisonment or death whereas in case of 'below 16 years and above 12 years' and '16 years and above' the punishment is lesser. Why? If the crime is the same, then, why should there be discrimination in case of punishment? That should not be there if you want to initiate a deterrent law. Somebody may agree or may not agree. Reports are published in a routine manner as if India is a rape country, which it is not. But, there is no doubt about it that the incidents of rape are increasing alarmingly in different parts of the country. Therefore, Sir, this is my humble submission to the Government. There are certain other things to be considered. Suppose, today, we pass this Bill, what would be its effect subsequently? This Parliament passes so many Bills but is the implementation part taken care of adequately? That is the moot question. How many cases are pending in the courts? How many cases? In the High Courts, 23 per cent of the cases have been pending for over ten years. Sir, 29 per cent of all cases have been pending between 2 and 5 years in High Courts. In the subordinate courts, over 8 per cent cases have been pending for

[Shri Sukhendu Sekhar Ray]

over 10 years. A maximum number of cases in subordinate courts, that is, 47 per cent have been pending for less than 2 years. Total number of pending cases in the lower courts is 1.2 crore. I am not giving the figure of High Courts. How many vacancies are there in the courts? We require more courts. We require more judges. Otherwise, we would pass this law and this law would never be implemented in the long run whatever we provide for, that within two months inquiry is to be completed, that within six months the case is to be disposed or whatever. This would have no impact because there would be no judge to decide upon. What is the case of Kolkata High Court? The highest proportion of vacancies among the High Courts, where sanctioned strength is over ten judges is in Kolkata, that is, 58 per cent vacancies. The total number of vacancies of judges is 42, highest in the country followed by Karnataka. This is an alarming situation in the courts. They do not have infrastructure. They do not have judges and cases are mounting. We are passing laws, there is no implementation and everybody is raising fingers at the parliamentarians. Everybody is pointing fingers at the Government. What would the Government do unless these things are improved? This will be a myth.

So, my suggestion would be — I am not mentioning the other legal points; there are so many legal points to discuss — that this Bill be referred to the Select Committee, Sir. That would be the best thing at the moment. Thank you, Sir.

MR. CHAIRMAN: Shri Ram Chandra Prasad Singh, not present. Now, Shrimati Jharna Das Baidya. Madam, you have four minutes.

SHRIMATI JHARNA DAS BAIDYA (Tripura): Sir, please give me five minutes.

MR. CHAIRMAN: No, no. We have to pass the Bill or take a decision either way. ...*(Interruptions)*... Shri Navaneethakrishnanji, please. ...*(Interruptions)*... I know that. ...*(Interruptions)*... That would be seen.

SHRIMATI JHARNA DAS BAIDYA: Sir, in the Criminal Law (Amendment) Bill, we reiterate that the opportunity to provide comprehensive justice for women, who have been subjected to sexual violence, should not be lost and call for their inclusion even at this stage. Some of the objections to the Bill, I would like to mention.

Sir, before going into whether death penalty would help matters, let us examine the existing State of affairs. After a long struggle, the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act was passed in 2012. It provides for punishment of up to ten years for 'aggravated penetrative sexual assault' and up to five years for 'aggravated sexual

assault. It lays down that special courts be set up, investigations be completed in three months, and trials in one year, as far as possible. Moreover, it lays down conduct of media, the need for in camera trails and includes a slew of measures to protect the child.

Sir, what is the experience? In 2016, a total of 36,022 cases were registered under the Act in India. The Police already had over 12,000 pending cases from 2015. So, in all they were looking at over 48,000 POCSO cases in 2016. They managed to dispose of nearly 33,000 of these cases by completing investigations and either by filing charge sheets or by other means. A third of the cases were pending again, to be carried on to the next year. This data from the National Crime Records Bureau is available till 2016 only. At the level of the courts too, pendency of cases has reached alarming proportions. The courts already had over 70,000 cases of child sexual abuse and rape pending, when nearly 31,000 more cases were added in 2016. So, they were facing over a lakh cases. They disposed of just about 11,000 cases, leaving 90,000 cases still pending. But, the worst part is that courts were able to convict the offenders only in three per cent of cases. Sir, that means seven in ten people accused of raping children are going scot free under the special law framed to deal with this heinous crime.

MR. CHAIRMAN: Right. Please complete.

SHRIMATI JHARNA DAS BAIDYA: The number of judges, courts and personnel required to deal with the cases is woefully inadequate.

MR. CHAIRMAN: Thank you. Please conclude.

SHRIMATI JHARNA DAS BAIDYA: Sir, I will take only one minute. In particular, the Ordinance seeks to cover up the deliberate delay and inaction by the Government in both the horrific Kathua and Unnao cases, in which the rapists acted with complete impunity as they were in a position of power. Both cases involved a complete breakdown of law and order.

MR. CHAIRMAN: Please, please. You are not supposed to read. नंबर 1, आपको पढ़ना नहीं चाहिए, नंबर 2, जितना टाइम दिया है, उतने टाइम में बोलिए।

SHRIMATI JHARNA DAS BAIDYA: Sir, apart from this, we demand that command responsibility must be recognized as recommended in the Verma Committee Report, and also demand that these changes should be incorporated in the final Act. Thank you, Sir.

MR. CHAIRMAN: Now, Prof. Manoj Kumar Jha. You have four minutes.

PROF. MANOJ KUMAR JHA (Bihar): Sir, I will probably take less than that. Sir, on the Criminal Law (Amendment) Bill 2018, I have a couple of issues which I am

[Prof. Manoj Kumar Jha]

flagging and putting before the two hon. Ministers here. Sir, the first is, the death penalty provisions, I have a fear, might endanger victim girl's life because the rapist might want to destroy the evidence if the punishment for murder and rape is one and the same. That is my fear. I do not know. The collective wisdom of the House shall deal with it. The rate of conviction in rape cases is already very low. Increasing the quantum of punishment might make the situation a little more precarious. New offences have been listed under IPC. When we go for any such move, do we undertake any study to show how and whether it will be more effective in new offences not being committed? I came across a fact that the prior sanction for prosecution of public servant for rape was earlier not there. I do not see any rationale behind it. Funding of legal and welfare services in tune with our mandate probably would have been much more appropriate. Sir, is it not a matter of collective shame for all of us that rape victims are not given a fresh piece of cloth when their clothes are collected as evidence? Sir, I think it is a matter of collective shame for us. Sir, I also remember that a rape kit was promised long ago. The whole generation which came on road in the name of Nirbhaya feels that they have been deceived. They feel very disappointed. In that context, if I look at the budgetary provisions made for Nirbhaya and what we have got,—what is very important and as one of my fellow Member has said here—I think we should have opted for engagement with POCSO which is, actually, gender-neutral. There are instances of massive sexual abuse with boys. That does not figure out there. These are the points of submissions. I am putting before the House and before the two hon. Ministers. Probably, they will take cognizance of it and something better would come out.

MR. CHAIRMAN: Now, Shri K.T.S. Tulsi. You have three minutes.

SHRI K.T.S. TULSI (Nominated): Sir, I am not opposed to enhancing punishment. But I believe that simply enhancing punishment does not solve any problem. Criminal justice machinery is in shambles and if we do not think of streamlining criminal justice, this will be another law which will become a paper tiger, and for that, merely prescribing time limit in law, has never proved to be sufficient. We have the experience of election petitions being decided after five years. We have the experience of people seeking divorce spending half of their lives despite the fact that the statutes in both these cases prescribe the time limit of six months. We cannot think that we have prescribed the time limit and, therefore, by some magic, justice will be done. Unless we provide tools of technology, justice will continue to move at a bullock cart's speed. And if it moves at a bullock cart's speed, there is no way we are going to be able to control crime or reduce crime. I submit

that there are various aspects of this law which have not been taken into account. We need to have very effective witness protection. Without the witness protection programme, courts will not be able to streamline justice. We also need every police station in the country to be provided with mobile forensic vans which will accompany the homicide teams to the spot and where all the evidences will be collected scientifically because it is only by reducing the dependence of oral evidence that criminal justice can actually be done. We cannot see this in compartment of criminal justice with regard to young girls. It is most heinous crime. But mere enhancement of punishment is not going to change anything on the ground. We need special courts, where the girls are protected in the sense that they can make a deposition in court without being confronted with the perpetrator of the crime. We also need protection homes not of the kind which are in news these days where every day we discover that in one State or the other, the girls who are meant to be in protective custody, are being exploited. So, unless there is a comprehensive plan drawn up, I don't see that there will be any concrete change in the ground reality, and for that, I submit that it will be for the good of the country if we refer it to a Select Committee.

MR. CHAIRMAN: Thank you. Now, Dr. Amee Yajnik. You have two minutes' time. I feel sorry. But, your party has got another three Members.

DR. AMEE YAJNIK (Gujarat): My name is there in the list.

MR. CHAIRMAN: Yes, your name is there. But, the only thing is, I have to give opportunity to others also. Your name is there in the list.

DR. AMEE YAJNIK: Thank you, Hon. Chairman, for giving me this opportunity. I have been hearing all the speakers, and I have also seen the Bill, and the amendment that is suggested. Sir, I think, it should be referred to a Select Committee for several reasons. We need some comprehensive submissions to be made in this Bill, because the time limit is prescribed for an appeal after the sentence is declared, but, there is no time limit for the trial. If the trial goes on for several years, what is the sense of having an appeal within six months, and then, we go to the Supreme Court. So, the multiplicity of appeals has not been dealt with here. That is one part.

Shortening the time of investigation, but, the investigation is done by the same officer who is also investigating the economic offences. The sensitivity part is not discussed anywhere. I think, that angle should be brought into this Bill, and that also is coupled with the fact that when the investigation is not over in two months, sixty days, there is a default bail, and the accused goes scot free, many of them. So, that is a second part. The third part is, what happens to the victim? In the POCSO Act there are elaborate

[Dr. Amee Yajnik]

provisions that the small girls, victims, have to be kept away from the perpetrators when they are brought to court. They have to be rehabilitated; they have to be counselled by psychologists and by people who can protect them, give them some assurances. Nothing is being done. Apart from this, the witness protection - that they are afraid of coming and deposing in the trial courts - these two aspects have to be dealt with very severely, in a very comprehensive way, and in detail.

And the last aspect that what happens when the courts are not there. The piling up of POCSO cases from the State I come, and the court is not there. These children are always brought in a huddle. They are put into the shelter homes. They don't know their fate. They don't even have come out of the trauma they have undergone. So, where are these aspects? How are we going to deal with it just by bringing an amendment, of bringing harsher punishment? So, this should be referred to a Select Committee, and all these objectives should be dealt with in a very detailed manner. Thank you, Sir.

श्री वीर सिंह (उत्तर प्रदेश): सभापति महोदय, मैं क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल, 2018 पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, सरकार पहले अध्यादेश लेकर आयी और और अब सदन में इस बिल को लेकर आयी है। आज देश में नाबालिग बच्चों के साथ यौन शोषण जैसी घटनाएं बढ़ी हैं, यह एक बहुत ही सोचने वाला विषय है। आज सख्त कानून बनाए गए हैं, कानून तो पहले भी सख्त था, किंतु उसका अनुपालन नहीं हो पा रहा था। जैसे कि निर्भया कांड हुआ था, निर्भया कांड के बाद सदन में चर्चा हुई, कानून बना, किंतु उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, इसलिए ये अपराध बढ़ रहे हैं। यदि हम सख्त कानून बनाएं और इस पर रोक लगाएं, तो इसका समाधान हो सकता है। आज हमारे देश में इस तरह के सबसे ज्यादा केस लंबित हैं, क्योंकि न्यायालयों की कमी है और न्यायालयों में जजों की कमी है। इसलिए आज ऐसे लाखों केस पेंडिंग हैं, हमें इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। जब इस तरह के अपराध होते हैं, उसमें गवाहों को गवाही देने से रोका जाता है, उनका संरक्षण नहीं किया जाता है, इससे भी अपराधी का मनोबल बढ़ता है। हमें उस ओर भी ध्यान देना चाहिए, जिससे कि हम ऐसी घटनाओं को रोक सकते हैं। इसके साथ-साथ, इसमें 16 साल की बच्ची या 12 साल या उससे कम उम्र की बच्ची के साथ ऐसा अपराध करने पर 20 साल की सज़ा या मौत की सज़ा का प्रोविज़न किया गया है। उसमें मौत की सज़ा का प्रोविज़न किया गया है। यह एक अच्छा कानून लाया गया है, एक अच्छा कदम है, इस पर अमल करना चाहिए। हम इसका समर्थन करते हैं, किंतु इस पर सख्ती बरतनी चाहिए, क्योंकि जब से केन्द्र और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है।...

श्री सभापति: पार्टीज़ का नाम लेने से वे लोग बोलेंगे।

श्री वीर सिंह: तो अपराधों में वृद्धि हुई है। ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: ठीक है, आपको कहना है?

श्री वीर सिंहः तो मैं यही चाहूंगा कि इसमें जो दूसरे सदस्यों ने सुझाव दिए हैं, इसको सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाए और इसमें ठीक प्रकार से बदलाव किया जाए।

श्री सभापतिः धन्यवाद। श्रीमती कहकशां परवीन।

श्रीमती कहकशां परवीन (बिहार)**:** सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आज मुझे इस बिल पर बोलने का मौका मिला, मैं इसके लिए अपनी पार्टी के नेता का शुक्रिया अदा करती हूं। मैं इस बिल का समर्थन करती हूं, वह इसलिए कि बहुत सारी लड़कियां हैं, जो यौन शोषण का शिकार होती हैं, उनकी रक्षा के लिए यह बिल पेश किया गया है। जब किसी बच्ची के साथ कोई घटना घटती है, तो उसके दिल में जो ज़ख्म बनते हैं या उसके माता-पिता के दिल पर जो चोट लगती है, वह जिंदगी भर नहीं भुलाई जा सकती है। इस बिल में जो प्रावधान किए गए हैं, मैं उनका समर्थन करती हूं। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि हम कानून बनाएं, लेकिन साथ ही साथ हम सोशल अवेयरनेस का भी काम करें। आज समाज कहां जा रहा है? आज रिश्ते भी पाक़ नहीं रहे हैं। जब बच्चियां स्कूल पढ़ने जाती हैं तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, जो अखबारों में आती हैं कि स्कूल में बच्चियों के साथ गलत हो गया। अगर बच्चियां किसी गाड़ी में स्कूल जाती हैं, तो वहां उनके साथ घटनाएं घट जाती हैं या फिर स्कूल में घटना घट जाती है। हम लोग कहते थे और संस्कृत में भी कहा गया है-

"गुरुर्ब्रह्मा, गुरुर्विष्णुः
गुरुर्देवो महेश्वरः।
गुरुर्साक्षात् परमं ब्रह्म
तस्मै श्री गुरवे नमः।।"

लेकिन आज जब हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं, तो मन में डर सा लगा रहता है कि कहीं स्कूल में भी हमारी बच्ची के साथ कोई घटना न घट जाए। जब तक हमारी बच्ची सुरक्षित घर नहीं पहुंच जाती है, तब तक हम परेशान रहते हैं। यह इल्ज़ाम लगाना, मैं इसे ठीक नहीं समझती हूं, चूंकि मैं एक सियासी पार्टी से आती हूं और यहां पर जो सारे लोग बैठे हैं, वे भी कहीं न कहीं, किसी दल से जुड़े हुए हैं। चाहे किसी की सरकार रहे, चाहे एनडीए की सरकार हो या यूपीए की सरकार हो, कोई यह नहीं कह सकता है कि हमारी सरकार में घटनाएं नहीं घट रही हैं या घटनाएं नहीं घटी हैं। इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता है। हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि हमारा समाज कहां जा रहा है और हमारे समाज के लोगों में चेतना जगाने के लिए हमें क्या प्रयास करना चाहिए, क्या पहल करनी चाहिए? आज हम लोगों को यह सब सोचने की जरूरत है। मैं आप लोगों से बस एक ही बात कहना चाहती हूं। सदन के सारे लोग यहां पर बैठे हैं कि जिसके साथ घटना घटती है, वह ज़िंदगी भर उस घटना को याद रखता है। उसके माता-पिता भी याद रखते हैं, लेकिन समाज की मुख्य धारा से वे बच्चे कभी जुड़ नहीं पाते हैं। समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम सभी को पहल करनी होगी और जब तक हम मिलकर कोशिश नहीं करेंगे, तब तक समाज जागेगा नहीं। तब तक इस तरह के जो यौन शोषण के मामले हैं, चाहे लड़कियों के साथ हो रहे हैं या लड़कों के साथ हो रहे हैं, इन पर हम सभी काबू नहीं पा सकते। माननीय मंत्री जी, इस संबंध में मेरा एक सुझाव है। जिस तरह से बिहार में महिला

[श्रीमती कहकशां परवीन]

थाना का गठन किया गया है, उसी तरह पूरे हिंदुस्तान में, हर राज्य में महिला थाना का गठन किया जाए। वह इसलिए किया जाए कि जब किसी लड़की के साथ कोई घटना घटती है या किसी औरत के साथ घटती है और जब वह थाने जाती है तो बहुत सारी बातें जो पुरुष पुलिसकर्मी होते हैं, उनके सामने खुलकर नहीं कह पाती है। अगर महिला थाना होगा, तो वे अपनी बातें खुलकर कहेंगी और उन्हें न्याय मिलेगा, बहुत-बहुत शुक्रिया।

†**محترمہ کہکشاں پروین (بہار):** سبھاپتی مہودے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آج مجھے اس بل پر بولنے کا موقع ملا، میں اس کے لیے اپنی پارٹی کے نیتا کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ میں اس بل کا سمرتھن کرتی ہوں، وہ اس لیے کہ بہت ساری لڑکیا ہیں، جو یون شوشن کا شکار ہوتی ہیں، ان کی رکشا کے لیے یہ بل پیش کیا گیا ہے۔ جب کسی بچی کے ساتھ کوئی گھٹنا گھٹتی ہے، تو اس کے دل میں جو زخم بنتے ہیں یا اس کے ماتا پتا کے دل پر جو چوٹ لگتی ہے، وہ زندگی بھر نہیں بھلائی جاسکتی ہے۔ اس بل میں جو پراؤدھان کئے گئے ہیں، میں ان کا سمرتھن کرتی ہوں۔ میں مانیئے منتری جی سے کہنا چاہونگی کہ ہم قانون بنائیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم سوشل اونیرنیس کا بھی کام کریں۔ آج سماج کہاں جارہا ہے؟ آج رشتے بھی پاک نہیں رہے ہیں۔ جب بچیاں اسکول پڑھنے جاتی ہیں تو ایسی بہت ساری گھٹنائیں ہیں، جو اخباروں میں آتی ہیں کہ اسکول میں بچیوں کے ساتھ غلط ہوگیا۔ اگر بچیاں کسی گاڑی سے اسکول جاتی ہیں، تو وہاں ان کے ساتھ گھٹنائیں گھٹ جاتی ہیں یا پھر اسکول میں گھٹنا گھٹ جاتی ہے۔ ہم لوگ کہتے تھے اور سنسکرت میں بھی کہا گیا ہے۔

''گرو برہما، گرووشنو:

گرودیوو، مہیشورا:

گروسرکشات پرم برھما

† Transliteration in Urdu script.

تسمے شری گروے نم:''

لیکن آج جب ہم بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں، تو من میں ڈر سا لگا رہتا ہے کہ کہیں اسکول میں بھی ہماری بچی کے ساتھ کوئی گھٹنا نہ گھٹ جائے۔ جب تک ہماری بچی سُرکشت گھر نہیں پہنچ جاتی ہے، تب تک ہم پریشان رہتے ہیں۔ یہ الزام لگانا، میں اسے ٹھیک نہیں سمجھتی ہوں، چوں کہ میں ایک سیاسی پارٹی سے آتی ہوں اور یہاں پر جو سارے لوگ بیٹھے ہیں، وہ بھی کہیں نہ کہیں، کسی دل سے جڑے ہوئے ہیں۔ چاہے کسی کی سرکار رہے، چاہے این ڈی اے کی سرکار ہو یا یوپی اے کی سرکار ہو، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہماری سرکار میں گھٹنائیں نہیں گھٹ رہی ہیں یا گھٹنائیں نہیں گھٹی ہیں۔ اس بات سے کوئی انکار نہیں کرسکتا ہے۔ ہمیں اس بات پر دھیان دینا ہوگا کہ ہمارا سماج کہاں جارہا ہے اور ہمارے سماج کے لوگوں میں چیتنا جگانے کے لیے ہمیں کیا پریاس کرنا چاہیئے، کیا پہل کرنی چاہیئے؟ آج ہم لوگوں کو یہ سب سوچنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ لوگوں سے بس ایک ہی بات کہنا چاہتی ہوں۔ سدن کے سارے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں کہ جس کے ساتھ گھٹنا گھٹتی ہے، وہ زندگھی بھر اس گھٹنا کو یاد رکھتا ہے۔ اس کے ماتا پتا بھی یاد رکھتے ہیں، لیکن سماج کی مکھیہ دھارا سے وہ بچے کبھی جڑنہیں پاتے ہیں۔ سماج کی مکھیہ دھارا سے جوڑنے کے لیے ہم سبھی کو پہل کرنی ہوگی اور جب تک ہم سبھی مل کر کوشش نہیں کریں گے، تب تک سماج جاگے گا نہیں۔ تب تک اس طرح کے جو یون شوشن کے معاملے ہیں، چاہے لڑکیوں کے ساتھ ہورہے ہیں یا لڑکوں کے ساتھ ہورہے ہیں، ان پر ہم کبھی قابو نہیں پاسکتے۔ مانیئے منتری جی، اس سمیندھ مین میرا ایک سجھاؤ ہے۔ جس طرح سے بہار میں مہیلا تھانہ کا گٹھن کیا گیا ہے، اسی طرح پورے ہندستان میں، ہر راجیہ میں مہیلا تھانہ کا گھٹن کیا جائے۔ وہ اس لیے کیا جائے کہ جب کسی لڑکی کے ساتھ کوئی گھٹنا گھٹتی ہے یا کسی عورت کے ساتھ گھٹتی ہے اور جب وہ تھانے جاتی ہے تو بہت ساری باتیں جو پروش پولیس کرمی ہوتے ہیں، ان کے سامنے کھلکر نہیں کہہ پاتی ہے۔ اگر مہیلا تھانہ ہوگا تو وہ اپنی باتیں کھل کر کہیں گی اور انہیں نیائے ملے گا، بہت بہت شکریہ۔

श्री सभापतिः धन्यवाद जी। श्रीमती वंदना चव्हाण।

SHRIMATI VANDANA CHAVAN: Sir, The crimes against women and children are on the rise in the country and the horrific nature of incidents has shocked the nation time and again. There can be no two thoughts that we have to protect our women, and children against all kinds of violence. Sir, I feel that at such times we tend to give a kneejerk reaction by enhancing punishments with little or no consideration to the ground reality whether the implementation of the present laws is being done properly. Sir, the issues, which I want to raise in this connection, I will make in bullet points so that I keep myself short. Sir, I have already submitted that on the one side we had the Indian Penal Code earlier, later noticing that there are several violence cases against children, the Legislature came out with special provisions, special legislation and the POCSO, which is meant only for children. Sir, in this case we see that most of the amendments that we seek to make under the Indian Penal Code are about rape on women below the age of 12, rape on women below the age of 16 years. So, Sir, I feel that instead of bringing an amendment in the Indian Penal Code, these amendments should have been under the POCSO because law has to have clarity. If you want to see any provision concerning children, it should have been under one law. Unfortunately, the lawyers or the people who want to defend or fight or prosecute will have to see two laws which was really not required. That is my submission. Second point, Sir, as some of my colleagues have already said, the provisions have mentioned the word 'woman'. Yes, it is true that under the IPC, under Section 10, a woman has been referred to as a 'female human being' of any age. But, Sir, in common parlance we see that a woman is an adult female. Therefore, in those days probably when the Indian Penal Code was there, there were not so many offences against children. Now with changed times, with changed number of offences happening against the children, number of legislations that we are making for children, Sir, I feel that the term 'woman' should be deleted because we cannot say when a two year old or a six year old child is raped, will we ever say that a woman has been raped? I think 'the child has been raped' will bring more consciousness and sensitivity amongst the people and legislators than saying that a six year old woman has been raped. Now we know, Sir, even a few months old children are raped, which is a very horrific thing. So, I make an appeal to the hon. Minister that this term needs to be changed. Even in the changed world, today the United Nations also talks about women and girls. Even the SDGs, for that matter, talk about women and girls. So, in that case that needs to be done. My third point again is that that this provision is gender bias. Why have we not applied this provision to the boys? Sir, in a recent survey in 2007 by the Ministry of Women and Child Development with sample of

12,447 children in families, schools, at work and living on streets, it was found that more than half had faced sexual abuse, and, shockingly, Sir, 53 per cent of the victims were boys. Even in my public life I have seen lesser number of girls who have been subjected to rape than the number of boys in the Observation Homes and Children's Homes. So, I think the boys need to be included. I don't know what kind of amendment probably in the near future the hon. Minister can bring about. Fourthly, Sir, for offences of rape on women under the age of 12, the legislation has prescribed death penalty, and, in this connection, Sir, I would make an appeal whether this will really help us to meet the ends of justice. Sir, I will like to draw the attention of the House and yourself to an NCRB Report, 2016 which reveals that 94 per cent of all cases registered under rape, rape with penetrative sexual assault on children were committed by people known to the victims such as family members, relatives, neighbours, employees, coworkers or other known persons. So, the person who helps the child to lodge a complaint is the parent and if the parent realises that it is a close relative, will he or she pursue the prosecution? So, I feel that this is something which will deter the parents from lodging the complaint. The Bill has already defined life imprisonment to mean the remainder of that person's natural life, meaning that there is no chance of releasing the accused early or on good behaviour which normally is done under life imprisonment. Why, Sir, should we slap a death sentence on such a person? My fourth submission, Sir, is strict and harsh punishment —there are so many lawyers here who will subscribe to my view — which means greater and stronger evidence on the one side, whereas under POCSO the law calls for child friendly procedures and to record evidence. Sir, in cross examinations in this case, if my client is going to be cnarged with life imprisonment or death, the lawyer in that case then, would go to any extent to cross examine the child and bring terror and fear in his mind and I don't think we will really be achieving the kind of benefit that we are looking for the victim. Sir, we are a country which respects human rights. There are some interesting statistics which show that death penalty falls on the marginalised and vulnerable due to police excesses. Those who have the economically deprived background, those who cannot afford lawyers, those who have undergone custodial torture and said to have given forced confessions, even Justice Verma Committee, Sir, in 2013 had deliberated on whether death penalty should be awarded. The Committee acknowledged that rape was indeed a violent crime, but it was possible...

MR. CHAIRMAN: Vandanaji, please conclude.

SHRIMATI VANDANA CHAVAN: Sir, please allow me to speak for just two minutes. This is a very important Bill.

MR. CHAIRMAN: Even the BJP has offered to give you three minutes. That is also over. Please conclude. You are making good points, but please conclude.

SHRIMATI VANDANA CHAVAN: Please, Sir, this is a very important issue and I would like to raise this. Otherwise, I will feel that I have not done my duty. Sir, please bear with me. The Committee supported enhanced punishment extending up to life imprisonment for rape, but not death penalty. Here we have enhanced the punishment, Sir, to remainder of that person's natural life. So, why hang him? That is my question. Sir, my last submission is, several other provisions regarding reducing the time limit for investigation from three to two months will result, according to me, in more acquittals as it will result in haphazard investigation or incomplete charge-sheet and all these will be detrimental to the outcome of the case, even the provision, Section 309 of the CrPC, and making it mandatory for the trial court to complete the trial in cases within two months. Also, Sir, trial courts have not been able to adhere to the time schedule even under the POCSO if we take review of that. I will not go into the details, but there are several aspects because of which the cops are not able to finish their cases even in one year. So, how can they do it in two months? These are some of my submissions. I make an appeal, Sir, that this Bill should be given to the Select Committee and a proper study is made. Thank you.

श्री सभापतिः श्रीमती छाया वर्मा। पार्टी में जो पुरुष सदस्य हैं, उनको महिला सदस्यों को अपना भी समय देना चाहिए।

श्री हुसैन दलवई (महाराष्ट्र)**:** सभापति महोदय, बिल के ऊपर बोलने के लिए restriction नहीं होनी चाहिए।

श्री सभापतिः किसी के ऊपर बोलने के लिए restriction नहीं होनी चाहिए।

श्रीमती छाया वर्मा (छत्तीसगढ़)**:** सभापति महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। मात्र कानून बना देने से ही समस्याओं का समाधान नहीं होता है। देश में बहुत कानून बनते हैं, लेकिन कानूनों का पालन कराने वाले अधिकारी होते हैं या वकील होते हैं। वकीलों के बारे में मैं कहना चाहूंगी,

"कानूनों के कान में ठोक जहर की कील
और हत्या कर दे सत्य की, वह है सफल वकील।"

महोदय, आजकल हर चीज़ व्यावसायिक हो गई है और कानूनों को तोड़-मरोड़ कर अपराधियों को बचाने का प्रयास हो रहा है। मैं इस संशोधन विधेयक में कुछ बिन्दुओं पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहती हूं। 12 वर्ष और 16 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं से यौनाचार करने वाले अपराधियों को आजीवन कारावास, मृत्युदण्ड और जुर्माने का प्रावधान इस विधेयक के जरिए लाया जा रहा है।

सर, इस बिल में 12 वर्ष और 16 वर्ष दोनों क्यों हैं? इसमें 12 वर्ष होना चाहिए या 16 वर्ष होना चाहिए। 12 वर्ष से कम या 16 वर्ष से ज्यादा, यह इसमें दृष्टिगत नहीं हो रहा है। इसलिए इसमें यह विरोधाभास नज़र आ रहा है।

दूसरा, यह भी साफ नहीं है कि जब बालक के साथ अपराध हो रहा है, तो अपराधी को कितनी सज़ा मिलेगी। मैं बताना चाहूंगी कि 53 प्रतिशत लड़कों के साथ भी बलात्कार के मामले होते हैं। उसमें तीन साल की सज़ा का प्रावधान है, लेकिन अगर लड़कियों के साथ यौनाचार का अपराध हो रहा है, तो मृत्युदण्ड या आजीवन कारावास की सज़ा का प्रावधान है। जब हम समानता की बात करते हैं, तो कम आयु की लड़के हों या लड़कियां हों, दोनों के लिए समान नियम होने चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। सर, आजकल फ़ेक न्यूज़ का बहुत चलन हो गया है। मैं इस संबंध में एक स्कूल का उदाहरण देना चाहूंगी। एक स्कूल में प्राध्यापक हैं, उनके स्कूल की एक महिला ने प्राध्यापक के ऊपर आरोप लगाया कि इस मास्टर ने मेरे साथ बलात्कार किया है। उस प्राध्यापक को आजीवन कारावास की सज़ा हुई। उस टीचर के माता-पिता जी ने आत्महत्या कर ली क्योंकि वे इस सदमे को बरदाश्त नहीं कर सके। कुछ दिन बाद वह प्राध्यापक जेल से बाहर आया और यह पता चला कि यह फेक न्यूज़ थी। उसके बाद होता यह है कि जिस महिला ने आरोप लगाया था, उसको 700 रुपये का अर्थ दंड देकर छोड़ दिया और उसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ। इस तरह से फ़ेक न्यूज़ हमारे देश में चल रही है।

श्री सभापतिः छाया वर्मा जी, ओ.के.।

श्रीमती छाया वर्माः सर, मैं एक मिनट और बोलना चाहूंगी।

श्री सभापतिः ठीक है, आप बोलिए।

श्रीमती छाया वर्माः सर, इसमें जो दो माह का नियम बनाया है, मैं बताना चाहूंगी कि इस दो माह में कोई भी जांच पूरी नहीं हो सकती है।। हमारे यहां महिला थाने में 33 प्रतिशत महिला पुलिस होनी चाहिए, लेकिन वहां पर सात प्रतिशत महिला पुलिस हैं। फोरेंसिक विशेषज्ञ, जो अपराधों के बारे में जांच करके बताते हैं, उनके बारे में बताना चाहूंगी कि हमारे देश में 4,340 फोरेंसिक विशेषज्ञ के पद खाली हैं, तो कहां से हम दो महीने में उसकी जांच कर पायेंगे?

अभी पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के बागपत का मामला आया था। वहां पर जेल में एक अपराधी ने दूसरे अपराधी को गोली से भून दिया। वहां पर जेल में ही अपराधी सुरक्षित नहीं हैं। जेलों में जरूरत से ज्यादा नियमों का उल्लंघन हो रहा है। मैं चाहती हूं कि इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाना चाहिए।

श्री सभापतिः श्री संजय सिंह, नहीं हैं। श्री तिरुची शिवा।

SHRI TIRUCHI SIVA (Tamil Nadu): Sir, this amendment is the need of the hour. I welcome this Bill, but with one or two reservations.

Sir, I don't want to say that the changing society is a deteriorating society. The victims of rape are not only female but also male. So, I think, rape should be defined gender-neutral. Many of my colleagues have expressed it earlier. But, I thought that it is a very important one and hence I am mentioning it again.

SHRI ANAND SHARMA: Sir, even transgenders are raped.

SHRI TIRUCHI SIVA: I am coming to that.

Sir, the Bill deals with rape on a woman under the age of sixteen years and girls under twelve years of age. However, the definition of 'rape' should be made gender-neutral. Even the Law Commission of India in 2000 and Justice Verma Committee in 2013 recommended for provisions regarding rape be applied equally to both male and female victims. But, the Bill, however, did not take it into consideration.

The purpose of a policy intervention should be to address the concerns of all, irrespective of gender. In this regard, the law is not inclusive. While the concern of the Bill to address the safety of girl child can be understood, this does not justify the Bill leaving out protection of males and transgender from rape. Sir, they are also subjected very much. The recent incidents across the country have raised a very big outcry from public and the Government, at the right point of time, has brought this amendment. But the difference is this. In the Act, punishment for raping a boy was seven years' life imprisonment. In this amendment, the punishment for raping a girl has been increased to ten years; whereas, for boys it remains the same — seven years! So also, for below twelve years, the imprisonment for raping a boy is ten years to life imprisonment. But, now, it is proposed to increase it to twenty years to life imprisonment when a girl is raped and not in case of boys. So, this should be taken into consideration. Despite the crime is similar, difference exists in imposing penalties. This difference is based merely on gender. This shows a lack of sensitivity on the part of the Bill not giving justice to minor male rape victims.

Sir, another point is relating to death penalty for rape and gang rape of girls of less than twelve years. Yesterday, there was a seminar conducted in Chennai about the abuse against girl child. What the women, in general, expressed was that death penalty means that the accused will immediately be hanged and there would not be any time for him to repent. He should be in prison lifelong only then no other person will dare to commit such crime was the observation made not only by NGOs but also by many parents. Suppose a person is punished with death penalty, he will die as soon as he is executed. There will be no time for him to repent. So, he should rather be put in prison for life. Only then the law will serve the purpose.

I will take just one more minute, Sir. The Criminal Law (Amendment) Bill, 2013, was passed by the Parliament in March, 2013, to amend the IPC in order to allow death penalty only in rape cases, where the accompanying brutality leads to death of the victim

or leads the victim into a persistent vegetative state, and also in case of repeated offences. Over the years, various court judgements have narrowed the application of death penalty only to the 'rarest of rare' cases. What I would suggest is, as have been proposed by many people across the country, such people should suffer in prison till their life, instead of hanging them to death. The death sentence is not a deterrent to committing crimes because of various socio-economic and procedural reasons. People tend to estimate that the probability of their being sentenced such a grave penalty is minimal. So, instead of punishing them with death penalty, they should be put in prison for life.

So, these are the two observations that I wanted to make for the consideration of the hon. Minister.

MR. CHAIRMAN: Now, Shri Husain Dalwai. You have only two minutes because four people have already spoken from your party.

श्री हुसैन दलवई: सभापति महोदय, जस्टिस वर्मा कमेटी की स्थापना की गई थी। उसने death penalty देना rarest of the rare कहा है। 94 केसेज़, जिन्हें किया गया उनमें से crime करने वाले जो victim थे, वे नजदीक के लोग थे। उनमें बहुत दफा तो परिवार के लोग होते हैं। उनमें बाप भी रहता है, चाचा भी रहता है, उसके और रिश्तेदार होते हैं तथा पड़ोसी होते हैं। इस प्रकार के बहुत से cases तो report ही नहीं होते हैं, क्योंकि वे नजदीक के ही लोग होते हैं, इसलिए बच्चों के ऊपर या बेटी के ऊपर बहुत pressure डाला जाता है, जिसके कारण ऐसे केसेज़ रिपोर्ट नहीं होते हैं, यदि आप इनमें डैथ पेनल्टी देंगे, तो मेरे ख्याल से ये केसेज़ रिपोर्ट ही नहीं होते। यह बड़ी चिन्ता की बात है। उसका conviction rate भी बहुत कम है। यदि डैथ पेनल्टी देंगे, तो कन्विक्शन रेट बढ़ेगा, लेकिन ऐसे केसेज़ में रिपोर्टिंग बहुत कम होगी, इस बात को भी हमें ध्यान रखना चाहिए।

महोदय, यहां गृह मंत्री जी बैठे हैं। मैं उन्हें अपने क्षेत्र का एक incident बताना चाहता हूं। मेरे घर में सुबह 3.00 बजे चार-पांच लोग आए। उनमें जिसने रेप किया था, वह भी था। उसका भाई मुझसे बार-बार कह रहा था कि मेरा भाई रेप कर ही नहीं सकता है। मेरा भाई ऐसा है और मेरा भाई वैसा है। मैंने कहा कि ठीक है, आप जरा पुलिस को फोन करके बताइए। वह बोला ठीक है, मैं बताउंगा। मैंने पुलिस को फोन नहीं किया, बल्कि लड़की के घर के आसपास जो लोग थे, उनसे मालूमात की कि आखिर क्या हुआ? मैं गृह मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि जब वह लड़की पुलिस स्टेशन गई, तो पुलिस वालों ने उसे पट्टे से खूब पीटा। जब मुझे इस बारे में पता चला, तो मैं, मेरी बीवी और हमारे कुछ कार्यकर्ता पुलिस स्टेशन गए, तब उसके बारे में इन्क्वायरी हुई और वह तीन साल के लिए जेल के अंदर गया। इसलिए इसमें खाली कानून बना देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि हमारे सिस्टम में बदलाव लाना बहुत जरूरी है।

महोदय, यहां हमारे Education Minister भी बैठे हुए हैं, मैं आपके माध्यम से उनके ध्यान में लाना चाहता हूं कि सेक्स के बारे में स्कूलों में भी education देना चाहिए, जिससे बच्चे समझें कि आखिर यह क्या मामला है। बहुत बार गलतफहमी की वजह से ये सारी बातें हो जाती हैं, इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए। मुझे बस इतना ही कहना था, धन्यवाद।

7.00 P.M.

MR. CHAIRMAN: Shri Binoy Viswam. You have only two minutes.

SHRI BINOY VISWAM (Kerala): Mr. Chairman, Sir, one more stringent Bill has come before us. We already have the POCSO Act and the Nirbhaya Act. And, now, this one is before us. But, it fails to address the real issue. The real issue is, the ideology of a patriarchal society is not good for women. This ideology has now become even more atrocious to everybody in the society. All the human values have today been overtaken by the market values. In markets, love, affection, the concept of family, everything has been thrown to the winds. So, nobody is safe even in their homes. The figures are very clear. In 94.6 percentage of the cases, who are the culprits? The victims are tortured by their close relatives, the men known to them. All those figures were mentioned here. I don't want to repeat them now. This is the real issue. So, with a major step of death penalty, we are not going to solve the issue. We want something more, something more objective and something more effective. So, the point is that this Bill needs a more study and a more careful observation about that. So, I request the House to refer this Bill to a Select Committee, which many Members have sought for.

MR. CHAIRMAN: Thank you.

SHRI BINOY VISWAM: Sir, there is one more point. Once it happens, the victims, 26 percentage of them, are dropped out from their schools. About 50 per cent of them and their families are forced to move away from their villages. They almost become refugees somewhere else. So, the social impacts, the psychological impacts, the human impacts, all these have to be considered with all seriousness. Sir, only for a propaganda leverage, such a Bill cannot be adopted.

MR. CHAIRMAN: You have made very salient points.

SHRI BINOY VISWAM: Thank you, Sir.

MR. CHAIRMAN: Now, hon. Minister.

SHRI KIREN RIJIJU: Hon. Chairman, Sir, first of all I would like to extend my gratitude to all the hon. Members who have given very substantive suggestions and contributing a lot to our understanding in dealing with this very sensitive matter. This is an extremely important subject. This is not a political issue, but this is a national issue, concerning our society, the morale of the society. So, cutting across the party lines, we all have converged together in talking about this important issue and coming together to pass

this important Bill. Sir, before coming to some of the important amendments which we have brought, let me quickly touch upon the objections being raised, not about the law but about some of the provisions and their request for submission to the Select Committee. Sir, this Bill has been extensively discussed in the Lok Sabha, and, now, it has come to this august House. First of all, Sir, the matter being raised about is the definition of – 'woman'. Sir, the term 'rape' traditionally had been focussed on woman. The 'Indian Penal Code has, specifically, dealt with the term 'woman'. That is why we have brought this particular amendment with the same word as 'woman'. It has already been mentioned, but let me repeat this. As per Section 10 of the IPC, the word 'woman' denotes a female human being of any age. So, flowing from that definition, we have come to this particular term in this particular amendment. But, I can assure the august House that it has been a long time since that we have this IPC, definitely, there will be a discussion in the Government, and we will give a relook and thinking about how this definition must be brought in the Indian Penal Code. Sir, with regard to the question on why only woman,

सर, इसमें यह कहा गया है कि जो Male बच्चे होते हैं, उनके साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं। मैं इसके लिए इस सदन को यह बताना चाहता हूं कि इस सरकार में महिला और बाल विकास मंत्रालय के माध्यम से एक केबिनेट नोट की तैयारी चल रही है। आप सभी को पता है कि जो "POCSO" कानून है, Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, that is a gender-neutral law. उस "POCSO" कानून में exhaustive, मतलब एक Total Relook दिया जा रहा है, जिसमें आपने डिटेल में यहां पर जो मैटर रेज़ किया है, उसका समाधान कर सकते हैं। आज का जो विषय है - क्योंकि देश में कुछ ऐसी घटनाएं हुईं, जिनमें दो साल से कम, पाँच साल से कम जो छोटी-छोटी बच्चियां हैं, उनको दृष्टिगत रखते हुए हमने टोटली डिफाइन किया है कि सोलह साल से नीचे और बारह साल से नीचे की बच्चियों के साथ जो इस तरह की घटनाएं हुई हैं, उनको देखते हुए सरकार ने यह समझा है कि ऐसे मामले, जो सामने आ रहे हैं, जिन पर देश में आवाज़ उठ रही है, समाज के हर तबके की ओर से आवाज़ उठ रही है कि, उन पर बहुत सख्ती से कानूनी प्रावधान लाने चाहिए। इसलिए हमारी सरकार के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, नरेन्द्र मोदी जी का यह विचार रहा है कि चूंकि पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा था, तो इसको एक Ordinance के form में लाना जरूरी था, इसलिए इसके लिए Ordinance लाया गया और आज इसको इस सदन में बिल के रूप में पेश किया जा रहा है।

सर, यहां victims protection की बात raise की गई है। मैं बताना चाहता हूं कि गृह मंत्रालय के माध्यम से victim and witness protection के लिए एक स्कीम चलाई जा रही है। सारी राज्य सरकारों को निर्देश भी दिया गया है कि यह जो स्कीम है, इसको सही तरीके से चलाया जाए। Victim and witness protection के लिए क्या-क्या प्रावधान होने चाहिए, इनको हमने डिटेल में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी दिया है।

[Shri Kiren Rijiju]

सर, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि इस सदन में समूचे देश की भावना उत्पन्न हुई है और सबने एक ही भावना के साथ बात रखी है। इसलिए मैं सिर्फ कुछ बिन्दुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सबसे पहले तो इसके लिए जो general provision है कि जब रेप होता है, तो उसके लिए सजा का क्या प्रावधान है। सबसे पहले IPC 376 में जो punishment का provision है, पहले यह 7 साल होता था, अब उसको 10 साल किया गया है। उसके बाद जो 16 साल से नीचे की बच्ची है, अगर उसके साथ बलात्कार होता है, तो उसके लिए पहले 10 साल की सज़ा होती थी, अब उसको minimum 20 साल किया गया है और उसके remainder of the life जेल में रहने का प्रावधान है। जो 12 साल से छोटी बच्ची है, अगर उसके साथ रेप होता है, तो उसके लिए पहले 10 साल की सज़ा होती थी, अब न्यूनतम 20 साल से rigorous imprisonment or death, इसमें नया प्रावधान रखा गया है। सर, मैं gang-rape के बारे में भी बताना चाहता हूं। Gang-rape में remainder of the life या death, उसके लिए ये दो प्रावधान रखे गए हैं।

सर, Section 173 CrPC के अनुसार पहले 3 महीने के अन्दर investigation complete करना पड़ता था, अब इस नए प्रावधान में इसे 'दो महीने' कर दिया गया है। इसके साथ ही पहले जो rape का trial चलता था, उसमें सिर्फ यह कहा जाता था कि as far as possible within two months, अब हमने इसको mandatory किया है कि दो महीने के अन्दर यह जो सारा investigation का process है, यह trial खत्म होना चाहिए। इस trial की भी deadline fix की गई है।

सर, यहां एक सबसे important बात कही गई है कि कोर्ट में केस बहुत लंबा चलता है। इसके लिए पहले जो disposal of the appeals होता था कि अगर कोई सजा दी गई है और उसके खिलाफ अपील होती है, तो उसके लिए कोई समय fix नहीं था। अब अपील में भी, कोर्ट में 6 महीने के अन्दर इस अपील के प्रावधान को भी complete किया जाना चाहिए। सर, मैं मानता हूं कि सरकार ने यह एक बहुत ही important कदम उठाया है।

सर, मैं anticipatory bail के बारे में कहना चाहता हूं कि पहले anticipatory bail का प्रावधान होता था, लेकिन अब इस मामले में anticipatory bail की कोई संभावना नहीं है। इसके बाद जब कोई अपराधी, जिसको accuse किया गया है, जब वह bail application move करता था, तो victim और उसके representative को पता नहीं चलता था। अब जब वह इसके लिए application देता है, तो उसको 15 दिन के अन्दर बताना जरूरी है। साथ-साथ जब कोर्ट में उसकी hearing होती है, तो उसके representative की मौजूदगी में उसकी hearing होने की आवश्यकता है।

सर, इसका जो consequential effect है, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं। मैंने ये जो IPC और CrPC के कुछ प्रावधान बताए, उनका जो consequential effect है, आप इसमें देखिए कि सरकार ने कितना सख्त कदम उठाया है।

सर, इस सम्बन्ध में महिलाओं के character के बारे में काफी ज़िक्र होता है, मीडिया में भी और समाज में भी। Indian Evidence Act के तहत अब यह कहा गया है कि महिलाओं के character के बारे में कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता है। कोई बलात्कार करेगा और उसका वकील कहेगा कि तुम्हारा

character ठीक नहीं है, तुम पुराने दिनों में कहाँ जाती थीं, क्या करती थीं। इस तरह का सवाल cross-examination में नहीं किया जा सकता है और न कोई उसका मायने रख सकता है। इसलिए अब previous experience की कोई जगह नहीं है। CrPC के Section 26 में यह कहा गया है कि उसका जो ट्रायल होगा, as far as possible, it should be by a woman Judge. हम लोगों के द्वारा यह नया प्रावधान डाला गया है। इसके अलावा पुलिस के पास जब ऐसा कोई मामला आएगा, तो उसकी जो complaint होगी, वह भी एक महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा ही record की जाएगी, यह नया प्रावधान भी इसमें डाला गया है। जो Statement record की जाती है, वह काम भी महिला अधिकारी ही करेगी। इसमें कहा गया है, "Statement of the victims shall be recorded by a Judicial Magistrate as soon as the commission of offence has been brought to the notice of the Police." हम लोगों ने इस तरह के जो women victim-sensitive measures उठाए हैं और जो नये प्रावधान रखे गए हैं, मैं मानता हूं कि इनका बहुत ही गहरा असर पड़ेगा।

दूसरा, अभी public servant के बारे में पूछा गया था कि अगर किसी public servant या पुलिस ऑफिसर की ओर से इस तरह की कोई घटना होती है, तो उसके बारे में क्या किया जाएगा? इस बारे में इसमें कहा गया है, Three shall be no previous sanction required for the prosecution of a public servant accused of the offence of rape. Public servant के बारे में अगर इस तरह का कोई मामला सामने आता है, तो उसके लिए previous sanction की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, rape cases में जो इंक्वायरी होगी या जो trial conduct किया जाएगा, वह in-camera किया जायेगा, ताकि उसमें कोई छेड़छाड़ न कर सके। हम लोग उसकी प्राइवेसी का भी ध्यान रखेंगे। The existing Section 357(B) of the CrPC says, "This amendment would ensure that the compensation scheme will be extended to the victims of the newly proposed categories." इसमें जो नया Section 376AB, Section, Section 376DA और Section 376DB है, इनमें यह provision भी रखा गया है कि इसमें compensation का पूरा benefit भी है। सर, Section 357C of the CrPC says, "All hospital, public or private, shall immediately provide first-aid or medical treatment free of cost to the victim of the offence of rape and shall immediately inform the Police." Through this amendment the facility of free first-aid or medical treatment shall be extended to the victims under the new proposed categories.

सर, मैं एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं, माननीय सदस्यों ने इस बात का जिक्र भी किया है कि सिर्फ कानून बना देने से ही वह ज़मीन तक नहीं पहुंचता है। अभी हमारे सभी माननीय सदस्यगणों ने ये सब बातें कही हैं और हम स्वयं भी यह मानते हैं कि सिर्फ कानून के प्रावधानों को बदल देने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता है। इसके लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 21 अप्रैल, 2018 को गृह मंत्रालय से एक cabinet proposal दिया, जिसके बाद Criminal Law (Amendment) Ordinance पास हुआ। उसमें और भी बहुत सारे important कदम उठाए गए हैं। अभी हमारे एक माननीय सदस्यगण ने Question किया था कि हमारी जो existing व्यवस्था है, उसको कैसे ठीक करना चाहिए। सर, हमें सबसे पहले देश भर में fast track special courts का गठन करना होगा

[Shri Kiren Rijiju]

और इसके लिए Centrally-funded scheme के proposal को announce भी कर दिया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब जहां-जहां भी कोर्ट नहीं बना है, वहां कोर्ट बनेगा और जहां बना हुआ है, उसको और मजबूत बनाने के लिए प्रावधान रखा गया है। इस मामले में हम राज्य सरकारों से और हिन्दुस्तान में जितने भी हाई कोर्ट्स हैं, उनसे भी चर्चा कर रहे हैं। यहां माननीय कानून मंत्री जी बैठे हुए हैं, उनके माध्यम से भी हमारे यहां जितने कोर्ट्स हैं, उन सबके साथ चर्चा कर रहे हैं।

सर, इसके बाद prosecution की जो मशीनरी है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे जितने भी States या Union Territories हैं, उनमें जो fast track special courts बनाए गए हैं, वहां public prosecutors, office infrastructure and supporting manpower के लिए जो posts sanction करनी थीं या जो-जो चीज़ें चाहिए थीं, उसके लिए भी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। इसके अलावा, quality of investigatin है, which is very important, क्योंकि अगर investigation की quality ठीक नहीं है, तो फिर जस्टिस नहीं मिलेगा। इसके लिए जो rate of conviction होता है, वह quality of investigation पर निर्भर करता है। इसके लिए adequate provisions for special forensic kits for rape cases are proposed to be made available in all the Police Stations as well as hospitals where such medico-legal cases are handled to improve the quality of forensic evidence and thereby strengthen the case of prosecution. Dedicated and trained manpower are to be provided for investigation of sexual offences in a time-bound manner. सर, forensic laboratories के बारे में जैसा मैंने बताया, उसके लिए हर राज्य में forensic laboratories होनी चाहिए, इसके लिए कदम उठाया जा चुका है। उसके लिए पिछले साल गृह मंत्री जी ने हमारे देश में पहली बार एक बहुत ही important Crime and Criminal Tracking Network System को लॉंच किया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह database का एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम है। इसलिए हिन्दुस्तान के अन्दर कोई sexual offender, जिसका अगर previous character ऐसा है, उसके लिए अगर हर पुलिस स्टेशन के साथ हमारा NCRB networking रखे और अगर हमारे पास database collection होगा, तो हम easily track कर सकते हैं कि किस आदमी ने ऐसा क्राइम किया है और सम्भवतः ऐसा कौन कर सकता है। इसके लिए यह व्यवस्था की गयी है।

सर, गृह मंत्रालय चूंकि एक बहुत बड़ा मंत्रालय है, इसमें महिलाओं के लिए बहुत सारे प्रावधान पहले से रखे गए थे, लेकिन हमारे गृह मंत्री, राजनाथ सिंह जी ने इसके लिए एक और बड़ा कदम उठाया है। सर, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि अब गृह मंत्रालय में इसके लिए एक डिवीज़न क्रिएट किया गया है, क्योंकि अलग-अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो एक Special Division create किया गया है, जो महिलाओं के लिए dedicated रहेगा। उसका नाम Women Safety Division है। महिलाओं से संबंधित जो भी सारी चीज़ें हैं, उनके लिए वहां पर अलग से एक dedicated Joint Secretary (Women Safety) appoint करके वह एक अलग Division create किया गया है। इसके अलावा, awareness पैदा करना, special Apps develop करना, Helpline, इस तरीके की बहुत-सी चीज़ें हैं, जिनको मैं यहां पर अभी नहीं बताना चाहता हूं, क्योंकि हमारे संबंधित माननीय सदस्यगण को इनकी जानकारी है।

सर, मैं आखिर में यह बताना चाहता हूं कि हमारे राष्ट्रपिता ने कहा था कि जब महिला रात के 12 बजे सड़कों पर अकेले चलेगी, तब हम मानेंगे कि हमारा देश सम्पूर्ण रूप से आज़ाद हो गया है, इसलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से यह कहा है कि हर माँ, हर पिता अपने बच्चे से यह पूछे कि आप कहां जाकर आये हो, आप क्या कर रहे हो? उनके काम से, उनकी हरकतों से समाज में हमें कहीं कोई शर्मिंदगी महसूस न हो, ऐसी घटनाएं न हों, इसके लिए हर परिवार को इस बारे में सोचना चाहिए।

मैं सरकार की तरफ से सदन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि Select Committee में इसे भेजने की कोई आवश्यकता मुझे नजर नहीं आ रही है। आपका जो भी concern है, उसके बारे में मैंने शॉर्ट में इसलिए बताया, क्योंकि आपको सब्जेक्ट की जानकारी पहले से है। लोक सभा में भी इस तरह की चर्चा होने के बाद पास होकर आज यह राज्य सभा में आया है, तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमने जो इतने अच्छे प्रावधान बनाये हैं, उनके बारे में आपको संक्षेप में बताया है, इसके अलावा, आपने जो-जो मैटर रेज़ किये, उनको address करने का भी आश्वासन मैंने दिया है, इस लिहाज़ से, मैं समझता हूं कि हम सब लोगों द्वारा अगर एक आवाज़ से इस Criminal Law (Amendent) Bill, 2018 को पास किया जाए, तो देश के लिए भी बहुत अच्छा होगा और एक अच्छा संदेश जाएगा। इसी अपील के साथ, मैं इस बिल को पास करने का निवेदन करता हूं।

MR. CHAIRMAN: Now, the question is:-

That the Bill further to amend the Indian Penal Code, Indian Evidence Act, 1872, the Code of Criminal Procedure. 1973 and the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: We shall now take up Clause-by-Clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 26 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: Now, Mr. Minister.

SHRI KIREN RIJIJU: Sir, I move:

That the Bill be passed.

The question was put and the motion was adopted.

SPECIAL MENTIONS

MR. CHAIRMAN: Now, Special Mentions. Shri P.L. Punia, not present. Shri Sambhaji Chhatrapati, not present. Shri R. Vaithilingam, not present. Shri K. Somaprasad.